#### **To Procure Entire Crop of Farmers**

\*702. Shri Jogi Ram Sihag, M.L.A.: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to made proper arrangements for procuring entire crop of farmers in State instead of implementing gate pass system togetherwith the details thereof?

# JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

No, Sir. Proper arrangements have been made for procuring entire crop of farmers cultivating paddy, bajra, maize, moong and groundnut at Minimum Support Price (MSP) and other crops through the gate pass system. Some problems were noticed in the gate pass system in the initial days of procurement which have since been resolved.

#### NOTE FOR PAD

#### **To Procure Entire Crop of Farmers**

## \*702. Shri Jogi Ram Sihag, M.L.A.

The HSAM Board was set up on 1<sup>st</sup> August, 1969 for exercising superintendence and control over the Market Committees in the Haryana State. Since inception, the Board has established 113 Principal Yards, 168 Sub Yards and 196 Purchase Centers to facilitate the procurement of food grains.

In order to ensure the procurement of food grains systematically and in a transparent manner, the HSAMB has started the electronic system for gate pass and auction during 2016. The Haryana State Agricultural Marketing Board has also started the 'Meri Fasal Mera Byora' portal for registration of farmers and their crops in the State during 2018. This portal has the provision for capturing the personal details of the farmers, their bank accounts, detail of crop sown and detail of the land as per revenue record. The provision for the verification of the crop data is also included in this portal by way of integrating it with the HARSAC and e-Girdawari portal of Revenue Department. The field level officers of the Agriculture Department are also engaged for verifying the details on the portal through their unique credentials in case of any mismatch on above data. The gate pass of the registered and verified farmers is being issued at the mandi gate and then processed for procurement of the food grains by the procurement agencies. The online portal for payment and receipt of procured material by the procurement agencies has also been implemented for transparency and facilitating timely payment directly to the Aarthias & Farmers. The data of major crops procured on MSP since 2018 is as under:-

Year	Name of Crop	Registered Farmer	Registered Land (In Acre)	No. of Gate Pass	Quantity (In Lakh MT)	Amount (In Crore)
2018	Bajra	147868	329721	81764	1.83	354
2019	Wheat	704272	154414	1152575	92.44	15172
	Mustard	243140	2086102	324537	6.13	2572
	Paddy	398102	On spot registration	1050686	64.68	11443
	Bajra	122750	638100	134123	3.11	620
2020	Wheat	505030	5232746	923777	74.06	14198
	Mustard	287439	1089303	298265	7.47	3307
	Paddy (upto 03.11.2020)	-	-	642123	49.43	9330.64

In order to streamline the process of procurement during the Pandemic COVID-19, the additional procurement centres were established and scheduling of farmers was done during Rabi-2020 procurement season due to which there was no congestion in the mandis and social distancing was ensured. In the current ongoing paddy season, the procedure for scheduling of farmers is also being followed to avoid congestion in the mandis. Advance information on scheduling is made available on website & farmers are allowed to alter the schedule to suit their convenience. This system also permits preferences to farmers of Haryana in Central MSP regime and exclusively for farmers of Haryana, where State extends support to the extent of 100% for its farmers from its own budget in PSS operations over & above the 25% support given by Government of India.

With the implementation of 'Meri Fasal Mera Byora' and electronic gate pass system at the entry gate of mandi, a system for procurement of entire crop of the farmers with a transparent and efficient manner has been established. So, there is no proposal under consideration of the government to make arrangements for procuring entire crop of the farmers in the State instead of implementing of gate pass system.

### किसानों की समस्त फसल की खरीद करना

\*702. श्री जोगी राम सिहाग, एम.एल.ए.: क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गेट पास प्रणाली लागू करने के बजाय राज्य में किसानों की समस्त फसल की खरीद के लिए उचित प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

# जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

जी नहीं, श्रीमान्। गेट पास प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी. ) पर धान, बाजरा, मक्का, मूंग तथा मूंगफली की खेती करने वाले किसानों की पूरी फसल की खरीद के लिए उचित व्यवस्था की गई है। खरीद के शुरुआती दिनों में गेट पास प्रणाली में कुछ समस्याएं ध्यान में आई जिनका समाधान किया जा चुका है।

# नोट फॉर पैड

# किसानों की समस्त फसल की खरीद करना \*702. श्री जोगी राम सिहाग, एमoएलoएo

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन 1 अगस्त, 1969 को राज्य की सभी मार्केट कमेटियों की देखरेख व नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। अब तक बोर्ड द्वारा राज्य में कृषि उत्पाद के खरीद की सुविधा प्रदान करने हेतू 113 मुख्य यार्ड, 168 सब यार्ड तथा 196 खरीद केन्दों की स्थापना की गई है।

कृषि उत्पाद की खरीद प्रकिया को सुचारु रुप से चलाने तथा पारदर्शिता स्निश्चित करने हेतू हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में इलेक्ट्रोनिक गेट पास तथा निलामी प्रक्रिया वर्ष 2016 में प्रारम्भ की गई। राज्य के सभी किसानों व उनकी फसल का ब्यौरा दर्ज करने हेतू हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल' प्रारम्भ किया गया। इस पोर्टल में किसानों की व्यक्तिगत सूचना, उनके बैंक खाते का विवरण, बोई गई फसल का विवरण तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि का विवरण दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। इस पोर्टल में फसल को सत्यापित करने का प्रावधान देने हेतू इसे एच.ए.आर.एस.ए.सी. (HARSAC) तथा राजस्व विभाग के ई-गिरदावरी पोर्टल से भी जोड़ा गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के निवारण हेतू कृषि विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को पोर्टल पर अपने एकीकृत पहचान द्वारा सत्यापित करने हेतू नियुक्त किया गया है। मंडी गेट पर पंजीकृत तथा सत्यापित किसानों की फसल के गेट पास जारी किए जाते है और इसके बाद खरीद एजेंसियों द्वारा फसल की खरीद प्रक्रिया की जाती है। पारदर्शिता स्निश्चित करने तथा किसानों व आढ़तियों को समय पर सीधा भुगतान करने हेतू खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदी गई कीमत फसल की प्राप्ति तथा के भूगतान के लिए

ऑन—लाईन प्रक्रिया लागू की गई है। वर्ष 2018 से अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	फसल का नाम	पंजीकृत किसान	पंजीकृत भूमि	गेट पास की संख्या	मात्रा	राशि (करोड़ में)
	1111	(संख्यां)	(एकड़ में)	राज्या	(लाख एम.टी. में)	(कराङ् म)
2018	बाजरा	147868	329721	81764	1.83	354
2019	गेहूँ	704272	154414	1152575	92.44	15172
	सरसों	243140	2086102	324537	6.13	2572
	धान	398102	मौके पर पंजीकरण	1050686	64.68	11443
	बाजरा	122750	638100	134123	3.11	620
2020	गेहूँ	505030	5232746	923777	74.06	14198
	सरसों	287439	1089303	298265	7.47	3307
	धान	_	_	642123	49.43	9330.64
	(03.11.20					
	तकं)					

कोविड—19 महामारी के दौरान खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतू रबी—2020 सीजन के दौरान अतिरिक्त खरीद केन्द्र बनाए गए तथा किसानों को निर्धारित समय पर बुलाया गया, जिसके कारण मंडियों में भीड़—भाड़ नहीं हुई तथा सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सकी। वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी किसानों को निर्धारित समय पर बुलाया जा रहा है, ताकि मंडियों में भीड़—भाड़ न हो। शैडयूलिंग की अग्रिम जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है और किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार शैडयूल में बदलाव करवाने की अनुमित दी गई है। यह प्रणाली केंद्रीय एम.एस.पी. व्यवस्था में विशेष रूप से हरियाणा राज्य के किसानों को प्राथमिकता देती है, जहाँ राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा दिए गए 25 प्रतिशत सहायता के उपर अपने बजट से अपने किसानों के लिए 100 प्रतिशत की सीमा तक प्राईस स्पोर्ट स्कीम के संचालन में सहायता देती है।

'मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल' तथा मंडी गेट पर इलेक्ट्रोनिक गेट पास प्रक्रिया लागू करके किसानों की पूरी फसल को खरीदने के लिए एक पारदर्शी तथा प्रभावी प्रणाली स्थापित की गई है। अतः बिना गेट पास प्रणाली के राज्य में किसानों की समस्त फसल की खरीद व्यवस्था हेतू कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।